प्राइवेट ट्यूशन विश्लेषण और विचार

लक्ष्मी नारायण मित्तल*

भारत सहित विश्व के सभी देशों के नीतिकार शिक्षा के संदर्भ में ज्यादातर औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर ही सरकारी नीतियाँ बनाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर जो नीतियाँ बनती हैं, उनमें प्राइवेट ट्यूशन पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। यद्यपि, यह प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा का एक आवश्यक अंग बन गया है। प्रस्तुत लेख में प्राइवेट ट्यूशन नामक संस्था की बढ़ती माँग और उससे होने वाली विद्यालयीन क्षतियों की चर्चा की गई है।

प्राइवेट ट्यूशन का प्रचलन भारत में आजकल कुछ अधिक ही देखने को मिलता है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर तो यह पिछले अनेक दशकों से चला आ रहा है, परंतु कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा में भी इसने घुसपैठ शुरू कर दी है और अब तो नर्सरी और किंडरगार्डन के विद्यार्थियों पर भी इसकी छाया पड़ने लगी है।

‘प्राइवेट ट्यूशन’ एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा प्रणाली की प्रतिछाया है।

सन् 1999 में पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग ने निजी शिक्षा के नाम से प्राइवेट ट्यूशन पर एक अध्ययन प्रकाशित किया था।

प्राइवेट ट्यूशन के लिए ‘प्रतिछाया’ शब्द बिल्कुल सटीक रूपक है। निजी पूरक ट्यूशन का

वजूद केवल इसलिए है, क्योंकि मुख्य शिक्षा प्रणाली मौजूद है। जैसे-जैसे मुख्य शिक्षा प्रणाली का रूप और विचार बदलता है उसी के अनुरूप प्राइवेट ट्यूशन का रूप भी बदल जाता है।

2007 आई.आई.ई.पी. पॉलिसी फ़ोरम के समापन में यह टिप्पणी की गई थी — प्राइवेट ट्यूशन का विस्तार सभी देशों और संस्कृतियों में तेजी से फैल रहा है। पूर्व हो या पश्चिम, धनी हों या निर्धन सभी देशों में शिक्षा का बाज़ारीकरण और निजीकरण अपने पैर पसार रहा है। इस फ़ोरम में अनेक देशों के उपस्थित प्रतिनिधियों ने इस उदगार को दोहराया है। पहले प्राइवेट ट्यूशन का कारोबार छिप कर किया जाता था, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन का कारोबार अब गोपनीय नहीं रहा है। यह कारोबार अंधेरे कोने से निकल कर उजाले में आ रहा है।

* पूर्व प्राचार्य एवं प्रोफ़ेसर, एच-899, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना – 476001

अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कारणों और परिस्थितियों के कारण प्राइवेट ट्यूटिंग को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए, रूस के कई पूर्व उपनिवेशों में इसका कारण है—मुख्यधारा के शिक्षकों का कम वेतन। उन्हें अपने परिवार के लालन-पालन के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत ढूँढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है। भारत के भी अनेक राज्यों में कमोबेश यही स्थिति है। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार, विकासशील देशों में स्कूली शिक्षा का एक तिहाई भाग गैर-सरकारी निजी स्कूल पूरा करते हैं। सरकारी स्कूलों की तुलना में इन निजी स्कूलों में कम वेतन के कारण यहाँ के शिक्षक ट्यूशन से अपनी आय वृद्धि करते हैं। भारत के अनेक राज्यों में सरकारी स्कूलों में कई बार शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है और उन्हें 'गुरुजी' 'अतिथि शिक्षक' के नाम से जाना जाता है। इन शिक्षकों को बहुत ही कम वेतन पर नियुक्त किया जाता है।

परंतु दूसरी ओर, विकसित देशों में जहाँ शिक्षकों का वेतन अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक है वहाँ सामाजिक प्रतिस्पर्धा और भावी सफलताओं की कामना ने प्राइवेट ट्यूशन की प्रणाली का विकास किया है। अमरीका और इंग्लैंड में कुछ सीमा तक कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का स्तर ऊँचा उठाने के लिए प्राइवेट ट्यूशन का चलन शुरू हुआ है, परंतु अन्य अनेक विकसित देशों में, यथा कनाडा आदि में, इसका उद्देश्य स्कूलों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर उनकी ऊँची रैंकिंग स्थापित करना है।

इसके विपरीत अफ्रीकी देशों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली के गिरते स्तर के कारण प्राइवेट ट्यूशन

को बढ़ावा मिला है। कितेव आई ने अपने आलेख 'प्राइवेट ट्यूटिंग एंड फ़ाइनेसिंग इशूज़' में लिखा है—कुछ देशों में सरकार द्वारा निःशुल्क प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण शिक्षा के स्तर पर गिरावट आई है और मुख्यधारा की शिक्षा के इस गिरते असर के कारण प्राइवेट ट्यूशन को बढ़ावा मिला है। लेखक ने यह आलेख आई.आई.ई.पी., पेरिस में सन् 2007 में 'वाक प्रजेन्टेशन' में प्रस्तुत किया था। लेख में आगे कहा गया है कि अभिभावक निःशुल्क शिक्षा के कारण बचे पैसे से प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च करने में हिचकिचाते नहीं हैं।

इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्यों निःशुल्क शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं? उदाहरण के लिए, बोत्सवाना सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक स्तर पर दोबारा फ़ीस लेना शुरू कर दिया है। (कितेव के उपरोक्त उल्लिखित लेख से)

यह ज़रूरी नहीं है कि सरकार द्वारा शिक्षा पर अधिक खर्च करने से परिवारों द्वारा निजी शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च में कमी आ जाएगी, पर कुछ सुधार अवश्य हो सकता है। अच्छे शिक्षक नियुक्त होंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत में पिछले पचास वर्षों में सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर के कारण निःशुल्क प्राइवेट ट्यूशन को कुछ अधिक ही बढ़ावा मिला है। प्रथम की 'असर' रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि विभिन्न कक्षाओं में अधिगम का जो न्यूनतम स्तर होना चाहिए उसके विपरीत छात्र अपनी कक्षा के नीचे की कक्षाओं का ज्ञान भी नहीं रखते हैं।

कुछ देशों में गैर-शैक्षणिक विषयों के लिए प्राइवेट ट्यूशन को बढ़ावा मिला है, जैसे — विकासवान देशों में नृत्य, पियानो बजाने, तैराकी या कुछ मुस्लिम देशों में धार्मिक शिक्षा के लिए। भारत में लड़कियों को स्वयं सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण देने के लिए प्राइवेट ट्यूशन की प्रणाली पर प्रशिक्षण कक्षाएँ लगती हैं। परंतु भारत सहित अधिकांश देशों में गणित, अंग्रेज़ी भाषा या विज्ञान के लिए प्राइवेट ट्यूशन को बढ़ावा दिया जाता है।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, संभवतः अब तक कोई ऐसा अध्ययन नहीं आया है जहाँ प्राइवेट ट्यूशन के विवरणों का व्याख्यात्मक अध्ययन हुआ हो; फिर भी यदा-कदा अखबारों की खबरों से कुछ विवरण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पिछले वर्ष बिहार में स्कूली स्तर पर बोर्ड परीक्षा में हुई धांधली के बाद अखबारों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि बिहार के स्कूलों में छात्रों का सर्वेक्षण करने पर विद्यार्थियों का कहना था कि स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विषयों की मात्र 40 प्रतिशत कक्षाएँ ही होती हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। यह सर्वेक्षण अनेक जिलों और प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हुआ है। जहाँनाबाद, सारन, लक्खीसराय, मधेपुरा, बाँका, वैशाली, दयालपुर आदि में संपन्न हुआ।

भारत के अनेक स्कूलों में पिछले एक दो वर्ष से छोटे-छोटे नगरों में 'स्मार्ट क्लासेस' और 'डे बोर्डिंग' के नाम पर कुछ अधिक समय तक स्कूल में बच्चों

को रोका जाता है और उनका होमवर्क वहीं करा दिया जाता है। यह मानो प्राइवेट ट्यूशन को संस्थागत बनाने का एक उपाय है। इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए सुधारात्मक कक्षाओं का आयोजन भी स्कूल में कर दिया जाता है। या तो इसके लिए अलग से अतिरिक्त शुल्क की माँग की जाती है या इस प्रकार के उपाय करने के लिए स्कूल को जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए पहले से ही कुल फ़ीस में यह भार जोड़ दिया जाता है।

भारत में कुछ बड़े शहरों में *पिकअप* करके प्राइवेट ट्यूशन के शिक्षा केंद्रों में पहुँचा दिया जाता है जहाँ वे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ शायद कुछ मनोरंजन भी करते हैं। बड़े शहरों में इस *पिकअप* व्यवस्था की बढ़ोतरी का एक कारण यह भी है कि माँ-बाप यदि दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चे को दोपहर बाद घर पर अकेले नहीं रहना पड़ता और माँ-बाप निश्चित रहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित वातावरण में है।

भारत में स्कूली स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार का दावा करने के बाद भी राज्य सरकारें इस बात का उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं कि कमजोर बच्चों की आवश्यकताओं को स्कूल की समय सारिणी में ही क्यों नहीं पूरा करा दिया जाता। इसके उल्टे अब तो छोटे-छोटे शहरों के अलावा गाँव-कस्बों तक प्राइवेट ट्यूशन के लिए 'कोचिंग संस्थान' खुल गए हैं। इस प्रकार के कोचिंग केंद्रों के विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं।

मुँरैना जैसे एक छोटे से नगर में ही एक मोहल्ले में ही कम से कम दर्जनों इस प्रकार के कोचिंग सेंटर हैं। ये

प्रातः 6 बजे से शाम 7 या 8 बजे तक चलते रहते हैं। राज्य सरकारें या स्थानीय प्रशासन इनकी उपस्थिति और आवश्यकता पर सैद्धांतिक चर्चा करके नीति बनाने के बजाय इनको 'रेगुलेट' करने के लिए स्थानीय स्तर का नियम बना लेती हैं यथा लड़के-लड़कियों की कक्षाएँ अलग से हों, वे विद्यार्थियों को पहचान पत्र दें, अपनी फ्रीस का बोर्ड लगाएँ, साफ़ पीने के पानी की व्यवस्था करें आदि। मूल प्रश्न यह है कि इस प्रकार कहीं प्राइवेट ट्यूशन का कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो किसी विद्यालय जैसा ही संचालित होता है, का औचित्य क्या है, इस पर किसी राज्य शासन या केंद्रीय शासन ने गंभीरता से चर्चा नहीं की है।

भारत में प्राइवेट ट्यूशन को संस्थागत बनाने के लिए स्कूल के बाद दोपहर के समय स्कूल में ही समूह में प्राइवेट ट्यूशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे अन्य प्रगतिशील बच्चों के स्तर तक आ सकें। इसके अलावा अनेक देशों में स्कूल के बाद बच्चों को स्कूल से 'पिकअप' करने और उन्हें 'निजी शिक्षा केंद्र' में ले जाने का चलन बढ़ा है। जहाँ दोपहर के शेष घंटों में पढ़ाई के साथ-साथ कुछ मनोरंजन के साधन भी जुटाए जाते हैं तथा उनके गृहकार्य को भी पूरा कराया जाता है। बच्चे ऐसे केंद्र में तब तक रहते हैं जब तक उनके माता-पिता काम से लौट कर उन्हें घर ले जाने के लिए नहीं आते। दोपहर के भोजन की जिम्मेदारी भी ऐसे निजी शिक्षा केंद्र लेते हैं।

कोई भी सरकार इस बात का उत्तर देने को तैयार नहीं है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की आवश्यकताओं को स्कूल ही स्वयं अपनी समय

सारिणी में क्यों नहीं पूरा करते? सरकारें अपने बचाव में अधिक रक्षात्मक रवैया अपनाती हैं और स्वयं बच्चों को इसके लिए दोषी मानती हैं। इसके विपरीत हार्टमैन ने मिस्र में किए अपने अध्ययन में एक विद्यार्थी की टिप्पणी का उल्लेख किया है जिसमें विद्यार्थी कहता है कि 'यदि मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया होता और केवल निजी शिक्षा लेता तो अधिक अच्छा होता।' व्यावहारिक रूप से कम से कम कुछ समाजों में प्रतिछाया अच्छी प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं। सिंगापुर में ट्यूशन केंद्रों ने मुख्यधारा के स्कूलों से आगे बढ़कर पाठ्यक्रम को पहले ही पूरा करा देने के प्रयास किए।

क्या प्राइवेट ट्यूशन सुंदर उद्यान में खरपतवार की भाँति हैं जो बालमन और शिक्षा के उस सुंदर पुष्प अथवा पौधे को नष्ट कर देता है?

असल सवाल यह है कि क्यों माता-पिता अपने बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन के लिए भेजते हैं और कभी-कभी अपने सामर्थ्य से बाहर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं? मुख्यधारा में ऐसी क्या कमी है जिसे ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान पूरा करते हैं, जहाँ कभी-कभी तो एक सौ या उससे भी अधिक बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जबकि मुख्यधारा के स्कूलों में कक्षाएँ खाली रह जाती हैं। छात्र स्कूली समय में प्राइवेट ट्यूशन पर जाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

नीति-निर्माताओं और योजनाओं को इस प्रतिछाया को केवल नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए, अपितु प्रौद्योगिकी में माहिर इन ट्यूटर्स से सबक लेना चाहिए, जो वीडियो पर ट्यूटोरियल बना कर बेचते हैं जिन्हें कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड

करके बच्चे कहीं भी आराम से देख और समझ सकते हैं।

क्या यह सही है कि प्राइवेट ट्यूटर अधिक तत्परता के साथ और अधिक व्याख्यात्मक रूप में पढ़ाते हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ प्राइवेट ट्यूटर यहाँ तक घोषणा करते हैं कि यदि आपका बच्चा अपेक्षित परीक्षा परिणाम नहीं पाता है तो आप अपनी फ़ीस वापिस ले सकते हैं?

संभवतः प्राइवेट ट्यूशन में छात्रों की योग्यता के अनुसार ग्रुप बनाए जाते हैं, जबकि औपचारिक शिक्षा प्रणाली की कक्षा में सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं।

भारत में प्राइवेट ट्यूशन के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू पर अध्ययन करने की आवश्यकता है और नीतिकारों को इसके नकारात्मक पक्ष के साथ-साथ इस प्रतिछाया शिक्षा प्रणाली के गुण-दोषों की व्याख्या करनी चाहिए।

निष्कर्ष

आखिर ये प्राइवेट ट्यूटर कौन होते हैं? भारतीय परिदृश्य की बात करें तो प्रायः ऐसे प्राइवेट ट्यूटर या तो 'क्लास टीचर' ही होता है, जो अपने विद्यार्थी की आवश्यकता (कमजोरी) को जानता है और इससे विद्यार्थी के अभिभावक को गुणवत्ता का आश्वासन रहता है। ऐसे अध्यापक से विद्यार्थी भी सहज रहता है और उसे बिना झिझक अपनी कठिनाई बताने और समझने का मौका मिल जाता है। या फिर उसी स्कूल का कोई अन्य शिक्षक भी हो सकता है, परंतु ऐसे में अनुभव किया गया है कि बच्चा अपने को असुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा भारत में प्राइवेट ट्यूशन में युवा भी जुड़े हैं, जो यद्यपि डिग्री

धारी हैं, परंतु बेरोजगार हैं और प्राइवेट ट्यूशन उन्हें कुछ अतिरिक्त धन प्राप्त कमाने का एक आसान तरीका समझ में आता है। हम सभी जानते हैं कि इससे गुणवत्ता का प्रायः अधिकांशतः अभाव रहता है। प्रायः छोटे नगरों में जहाँ अभिभावक उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, ट्यूशन सत्रों की गुणवत्ता पर नज़र रखना अधिक कठिन होता है।

निजी शिक्षक संस्थानों में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जा सकता। ऐसे में प्राइवेट ट्यूशन के सत्रों की गुणवत्ता पर नज़र रखना कठिन होता है।

प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा को भारत में प्रायः विवादास्पद रूप में ही देखा जाता है यद्यपि अब इसका एक विस्तृत रूप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की तैयारी के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत में मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों के अलावा राजस्थान का एक छोटा 'शहर' कोटा इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा दावा किया जाता है कि आई.आई.टी. या आई.आई.एम. से नौकरी छोड़कर बहुत अधिक प्रतिभावान योग्य शिक्षक ऐसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं जिनका वेतन आई.आई.टी. आदि की तुलना में अधिक होता है। यह एक प्रकार का बाज़ार है और प्राइवेट ट्यूशन 'इंडस्ट्री'।

प्राइवेट ट्यूशन पर अकसर आरोप लगता है कि इसने शिक्षा का बाज़ारीकरण कर दिया है। कभी प्राइवेट ट्यूशन का कारोबार भारत में छिपकर किया जाता था, परंतु अब यह गोपनीय नहीं रह गया है और इस निजीकरण ने इसे एक संपन्न व्यापार या व्यवसाय बना दिया है।

इस प्रकार की निजी शिक्षण व्यवस्था को समाप्त करना क्या भारत में आसान होगा? इसका संबंध प्रच्छन्न रूप से भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा है। दिसंबर 2016 में न्यूयॉर्क के पी.ई.डब्ल्यू. रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार संसार में भारत में 'Educational attainment' सबसे निचले स्तर पर है। इस अध्ययन में यूनेस्को द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर स्कूली शिक्षा की समीक्षा की जाती है। सन् 2011 के हॉवर्ड विश्वविद्यालय की आर.जे. बैरो रिपोर्ट और 2016 की कोरिया के जे.डब्ल्यू. ली की रिपोर्ट भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची है कि भारत में स्कूली स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता निम्नतम है। कुछ वर्ष पहले पिसा (PISA) ने 110 देशों में शिक्षा की

गुणवत्ता के अध्ययन में पाया था कि भारत नीचे से दूसरे स्थान पर है यानि अंतिम पायदान से एक सीढ़ी ऊपर (सबसे पीछे कर्गिस्तान है)। एन.एस.एस.ओ. की 2015 की वार्षिक रिपोर्ट में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में सेकेंडरी स्तर पर अधिगम के स्तर पर बहुत गिरावट देखी गई है। अभी हाल में दिल्ली के स्कूलों पर इसी प्रकार के अध्ययन में पाया गया कि 54 प्रतिशत विद्यार्थी एक वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। ऐसी परिस्थिति में प्राइवेट ट्यूशन की निजी शिक्षा की प्रथा को समाप्त करना शायद आसान नहीं होगा। नीति-निर्माताओं को सोचना होगा कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इस प्रतिछाया व्यवस्था से कैसे जूझा जाए। सरकार अपने बचाव में रक्षात्मक रवैया अपनाने के स्थान पर व्यावहारिकता सोचें।

संदर्भ

- असर की रिपोर्ट 2014 <http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER Reports/ASER 2014/National PPTs/aser2014indiaenglish.pdf> पर ऑनलाइन देखा गया।
- कितेव, आई. 2007. *प्राइवेट ट्यूटिंग एंड फ़ाइनेसिंग इशूज*. आई.आई.ई.पी., पेरिस.
- यूनेस्को. 2009. *प्राइवेट सप्लीमेंट्री ट्यूटिंग इन सेंट्रल एशिया*. यूनेस्को, पेरिस.
- सिलोवा, आई. और अन्य. 2009. *एजुकेशन इन अ हिडन मार्केट प्लेस — मोनिटरिंग ऑफ़ प्राइवेट ट्यूटिंग*. न्यूयॉर्क ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क.
- हार्टमैन, एस. 2008. *द इन्फ़ोर्मल मार्केट ऑफ़ एजुकेशन इन ईजिप्ट*. <https://www.ifeas.uni-mainz.de/Dateien/AP88.pdf> पर ऑनलाइन देखा गया।